एक नजर में

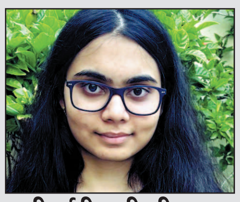

सीयूईटी यूजी की छात्रा बनी ऑल इंडिया टॉपर

नई दिल्ली. सीयूईटी यूजी 2026 के परिणामों ने इस वर्ष देशभर में शिक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लाखों उम्मीदवारों के बीच छात्रा अनन्या जैन ने ऑल इंडिया टॉप कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि परीक्षा में प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे देशभर के 11.64 लाख से अधिक उम्मीदवारों का इंतजार समाप्त हो गया है. इस वर्ष परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने भाग लिया, जिसमें कुल 15,68,867 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. जो लगभग 15 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है. यूजी में एक छात्रा ने देशभर में ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल कर सबका ध्यान आकर्षित किया है. उसने 1232.19 अंक प्राप्त किए, जो इस वर्ष का सबसे उच्चतम स्कोर माना जा रहा है.

शादी में गए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या

शिवपुरी. जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के खजरा गांव में एक युवक की पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई. युवक शादी समारोह में शामिल होने आया था. उसका शव गांव के बाहर पड़ा मिला. घटनास्थल से खून से सना पत्थर और एक खाली शराब की बोतल बरामद हुई है. पुलिस ने मृतक के साथ आए दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतक की पहचान शिवपुरी शहर के गौशाला क्षेत्र निवासी सुशील उर्फ शिम्पल उपाध्याय के रूप में हुई है. वह शिवपुरी-गुना बायपास स्थित सूर्या होटल में काम करता था. इसी होटल में उसके दोस्त शेषराम गुर्जर और कल्लू आदिवासी भी कार्यरत थे. कल्लू आदिवासी ग्राम बंगला, थाना बामौरकला का निवासी है. उसकी बेटी खजरा गांव में अपनी ननिहाल में रहती है. गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कल्लू, सुशील और शेषराम शिवपुरी से खजरा पहुंचे थे. तीनों युवक गांव के बाहर गए थे, जहां उन्होंने शराब पार्टी की थी.

तीन वर्ष तक अपग्रेड होंगे मिडिल और हाईस्कूल : सीएम डॉ. यादव

कैबिनेट ने दी मंजूरी

हर वर्ष अपग्रेड होंगे

75 मिडिल स्कूल

100 हाई स्कूल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 जून. प्रदेश के लगातार तीन वर्ष तक मिडिल और हाईस्कूल को अपग्रेड किया जाएगा. हर वर्ष 75 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और 100 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में तब्दील किया जाएगा. इस तरह तीन वर्ष में कुल 225 मिडिल और 300 हाईस्कूल को अपग्रेड किया जाएगा.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. ये सिलसिला इसी सीजन वर्ष 2026-27 से शुरू होगा, जो कि वर्ष 2028-29 तक चलेगा. इन स्कूलों को अपग्रेड करने पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. ये कवायद वर्ष 2029 तक 100 फीसदी नामांकन दर हासिल करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है मापदण्डों के आधार पर जिला स्तर से मैपिंग अनुसार 315 हाई स्कूल एवं 214 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की जरुरत है. कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि अब सांदीपनि विद्यालयों के कैचमेंट एरिया में विद्यालयों को अपग्रेड नहीं किया जाएगा. सांदीपनि विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में होने पर विद्यालय को अन्य आवश्यकता वाले स्थानों पर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा. अपग्रेड विद्यालय अपने वर्तमान भवन या अन्य शासकीय भवन में संचालित होंगे. आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किए जाएंगे. यहां बता दें कि राज्य में हाई स्कूल का सकल नामांकन दर 75 प्रतिशत तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर 55 प्रतिशत है. कक्षा 8 से 9 में कक्षांतरण दर 77 प्रतिशत और कक्षा 10 से 11 में 68 प्रतिशत है. विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण विद्यार्थियों का प्रवेश कम होता है या वे नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते, जिससे ड्रॉप आउट दर बढ़ती है. इसलिए विद्यार्थियों की पहुंच में विद्यालय उपलब्ध कराकर उच्च नामांकन एवं निरंतरता सुनिश्चित करना इस निर्णय का मूल लक्ष्य है.

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को एक अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्ष तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील है. योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. योजना के तहत गरीब जरूरतमंद, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में राशि 55 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से दी जाती है.

यह निर्णय भी लिए

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 हजार 580 करोड़ 7 लाख रूपये की स्वीकृति.
- पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विद्युतीकरण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा.

0% ब्याज दर वाले कर्ज के लिए ड्यू डेट एक ही रहेगी

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए जीरो फीसदी ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना के तहत नई शर्तों को मंजूरी दी है. निर्णय के तहत अब खरीफ एवं रबी सीजन के लिए अलग- अलग ड्यू डेट नहीं रखते हुए उसके स्थान पर वार्षिक एकल ऋण सीमा रखी जाएगी, जिसमें नगद एवं वस्तु ऋण की उप-सीमा निर्धारित रहे. योजना के तहत ड्यू डेट कृषकों को स्वीकृत वार्षिक एकल लिमिट से प्रथम ऋण आहरण से 12 माह निर्धारित की जाएगी और अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को 1.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. इससे डिफॉल्टर किसानों की संख्या में कमी आने की संभावना है.

म्यूल अकाउंट्स में करोड़ों का ट्रांजेक्शन

- 36 थानों में तफ्तीश शुरू, ओमती में जाली खाते खुले
- रांझी, अधारताल में एफआईआर की तैयारी

जबलपुर, 23 जून. म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की ठगी की रकम को खपाने वाले डेढ़ हजार खाते पुलिस ने चिन्हित कर लिए है. इन खातों की जांच शहर से लेकर ग्रामीण अंचल की पुलिस कर रही है. पांच सौ खातों से अधिक खातों के ट्रांजेक्शन का ब्यौरा खंगाला जा रहा है.

शहर के 22 तो ग्रामीण अंचल के 14 थानों में म्युल खातों की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. एक-एक खाते की जांच हो रही है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि जिसके नाम से खाता है, वह भी फर्जीवाड़े में शामिल है या उसे गुमराह कर खाता खुलवाया गया है. इसके बाद बैंकों के सहयोग से यह पता किया जा रहा है कि कहां से कब कितनी राशि आई और कहां ट्रांसफर की गई. इससे फर्जीवाड़े में कौन-कौन शामिल है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी खातों के तार अफ्रीकी देशों सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय ठिकानों से जुड़ रहे है. ओमती थाने में सर्वाधिक जाली खातों की जांच लंबित है. जबकि रांझी, अधारताल थाने में जांचों ने रफ्तार पकड़ ली है और एफआईआर की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा अन्य थानों में भी जाली खातों की जांच पड़ताल चल रही है. जिन भी म्युल खातों की साइबर फ्रॉड में संलिप्तता पाई जाएगी,उनके खाताधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है.

प्रलोभन-लालच देकर खुलवाए गए खाते

मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, जरूरतमंदों को कमाई, बेरोजगारों को लोन, कमीशन का लालच देकर उनके खाते खुलवाए गए. ठगों ने उन्हें भरोसे में लेकर दस्तावेज ले लिए और खाता खुलवाने के लिए उनके मोबाइल नंबर का उपयोग किया था. उनसे ओटीपी लेकर ठगों ने खातों में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया और खुद खाते को संचालित किया.

एसबीसी चुनाव : भोपाल-बुरहानपुर की मतगणना पूरी

जबलपुर. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन-2026 की मतगणना पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जारी है. निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 22 जून को शुरू हुई भोपाल जिले की मतपेटियों की गिनती मंगलवार को पूरी कर ली गई. इसके साथ ही बुरहानपुर जिले की मतपेटियों की मतगणना भी संपन्न हो गई. अब तक हुई मतगणना के आधार पर पांच प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं. इनमें राजेश व्यास, डॉ. विजय कुमार चौधरी, डॉ. पीसी कोठारी, महेश कुमार मौर्य और मोहम्मद महबूब अंसारी प्रमुख हैं.

यथास्थिति आदेश के बावजूद जारी राजस्व आदेशों पर रोक

जबलपुर, 23 जून. हाईकोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत याचिका में बैतूल निवासी मूलचंद ने निचली अदालतों के उन आदेशों को चुनौती दी है, जो एक ही खसरा नंबर की भूमि से संबंधित बताए गए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित भूमि को लेकर वर्ष 2018 की एक रिट याचिका में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही वर्ष 2019 में दायर द्वितीय अपील भी लंबित है, जिसमें निचली अदालतों का रिकॉर्ड तलब किया जा चुका है। इसके बावजूद अधिकारियों ने विवादित आदेश पारित कर दिए. राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों के बाद न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

ग्रामीण स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर फोकस

- उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य नीति पर विमर्श
- मेगा स्वास्थ्य नीति-2026 पर मंत्रिपरिषद समिति की चर्चा

भोपाल, 23 जून. उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में मध्यप्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद समिति ने विमर्श किया.

बैठक में प्रस्तावित नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और समिति के सदस्यों ने नीति को जन-केंद्रित, सेवा-उन्मुख, गरीब एवं वंचित वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए. बैठक में मंत्रिपरिषद समिति के सदस्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह सहित अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अशोक बर्णवाल, आयुक्त धनराजू एस तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना समय की आवश्यकता है. विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परोपकारी संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है.

छात्रावास में भवन सुधार का कार्य तत्काल कराएं : अध्यक्ष जाटव

रीवा, 23 जून. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव रीवा जिले के भ्रमण के दौरान स्कूलों तथा छात्रावासों का निरीक्षण किया.

अध्यक्ष ने शासकीय पीके सांदीपनि विद्यालय तथा शासकीय एसके हायर सेकण्डरी स्कूल का निरीक्षण करते हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने प्राचार्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कक्षा आठवीं के बाद ही कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन दें. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएं.

बार-बार ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए पांच आरोपी केंद्रीय जेल इंदौर भेजे

- समाज को नशामुक्त बनाने के लिए रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

रतलाम। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रतलाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आदतन तस्करों को पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत निरुद्ध कर केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया है।

पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी बार-बार नशे की तस्करी में संलिप्त पाए गए थे और समाज में अपराध व नशे के फैलाव को रोकने के लिए इन पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार एवं राकेश पंद्रो के मार्गदर्शन में जिलेभर में ऐसे आरोपियों की पहचान की गई, जो लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय थे।

वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध कर केंद्रीय जेल इंदौर में भेजा है। निरोधात्मक कार्रवाई जिन आरोपियों पर की गई उनमें जावरा निवासी मुजफ्फर उर्फ मुज्जा, कालूखेड़ा क्षेत्र के रिछादेवड़ा निवासी दिनेश, पिपलौदा थाना क्षेत्र के धतुरिया निवासी मांगीलाल कीर, जेठाना निवासी मुकेश बैरागी तथा बरखेड़ाकला थाना क्षेत्र के कराड़िया निवासी मोहनलाल पाटीदार शामिल हैं।

इस कार्रवाई में जावरा शहर थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक मंडलोई, कालूखेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह चौहान, पिपलौदा थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश कोली, बरखेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक पतिराम डावरे, उप निरीक्षक राजश्री सिसोदिया, प्रधान आरक्षक अनीश सिंह तथा आरक्षक विकास पालीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रतलाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर भविष्य में भी इसी तरह कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हेड कांस्टेबल पर लव जिहाद का आरोप

कोतवाली थाने पर हिंदू जागरण मंच का जोरदार प्रदर्शन

नवभारत न्यूज़

खंडवा। कथित लव जिहाद के मामले को लेकर मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी और हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई तथा एक फरार युवक की गिरफ्तारी की मांग की। जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि 17 जून को संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोटवाड़ा रोड स्थित जंगल क्षेत्र में एक युवती और दो युवकों को पकड़ा था।

सूचना पर पहुंची पुलिस को पता चला कि युवकों में से एक शोएब अली, कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल इरशाद अली का बेटा है। मामले में पुलिस ने शोएब अली के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया था।संगठन का आरोप था कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई और हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर सीएसपी अभिनव बारंगे मौके पर पहुंचे और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल इरशाद अली को लाइन अटैच किए जाने की जानकारी दी तथा फरार आरोपी की तलाश जारी होने का आश्वासन दिया। कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। पुलिस के अनुसार मामले में युवती की ओर से किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि फरार युवक की तलाश के प्रयास जारी हैं।

शादी के फेरे के बाद शिकायत लेकर थाने पहुंच गई दुल्हन

ग्वालियर, 23 जून. डबरा नगर में कुछ अलग ही हुआ. यहां दुल्हन विदा से पहले हाथों में मेंहदी लगाए सीधे डबरा सिटी थाना पहुंच गई. दुल्हन लवली वाल्मीकि ने परिजनों के साथ पहुंचकर शिकायत की कि सामूहिक विवाह कराने वाली समिति ने जो सामान देने को कहा था, वह नहीं दिया. इसमें बाइक भी शामिल है. जब तक उसे बाइक नहीं मिलेगी, वह विदा होकर अपनी ससुराल नहीं जाएगी.

दरअसल, ईशानी शिक्षा एवं जनकल्याण समिति द्वारा डबरा में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया जा रहा था. संस्था ने सभी जोड़ों को मोटरसाइकिल सहित गृहस्थी का सभी सामान देने का वादा किया था. वहीं, संस्था द्वारा कन्या पक्ष और वर पक्ष से 10-10 हजार रुपये पंजीयन के नाम पर लिए गए.

जब ठगा महसूस हुआ तो पहुंचे थाने

दुल्हन के परिजन अपने आप को ठगा महसूस करने लगे और तब जाकर दुल्हन खुद लाल जोड़े में विदाई से पहले सिटी थाना पहुंची और संस्था के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई.

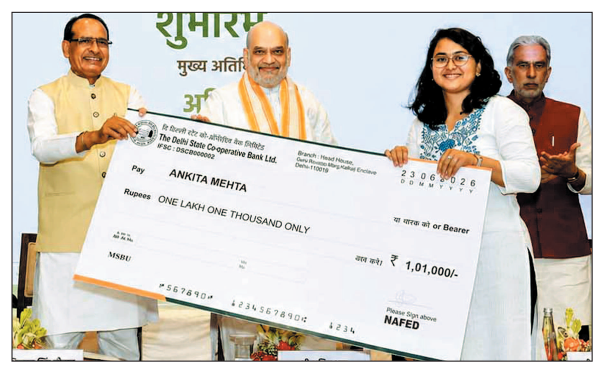

बिचौलियों की भूमिका होगी कम किसानों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, 23 जून. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के ऑक्शन पोर्टल एनएएफईएक्स डॉट इन की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'नाफेड' ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण के रूप में चार पहलों की शुरुआत की है.

उन्होंने कहा कि जो नाफेड 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, वह आज 500 करोड़ मुनाफे और 30 हजार करोड़ टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सहायता कर रहा है. 2014 में नाफेड गहरे आर्थिक संकट मे था. नाफेड के अधिकारियों ने पीएम मोदी के साथ बैठक की. इसके बाद भारत सरकार ने आर्थिक मदद करके नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू किया. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था. मुझे पता है कि नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था. आने वाले दो वर्षों में सहकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा दलहन का एक दाना भी व्यापारियों के माध्यम से न आए बल्कि सीधे किसानों के पास से आए. इससे किसानों को सीधा मुनाफा पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि जैसे ही दलहन का दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे खरीद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है. मेरा मानना है कि नाफेड की ओर से भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे.

अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरे जैसे कई भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 23 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के सूत्र को चरितार्थ और देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के बड़े नेता रहे हैं. उन्होंने प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कुछ किया, उसके दूरगामी परिणाम रहे. अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की अखंडता के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया.

राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थित पर फैसला आज

जबलपुर. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि में प्रकरण के प्रकरण में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे. राहुल गांधी की तरफ से व्यक्तिगत उपस्थित की छूट की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के निर्देश जारी किये है.

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में

राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची. एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट की ष्यरण्ली थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने निर्देश जारी किये थे.

संवाद | विकसित भारत 2047 में युवा सिविल सेवकों की अहम भूमिका

हर फाइल के पीछे लोगों की जिंदगी जुड़ी है : मोदी

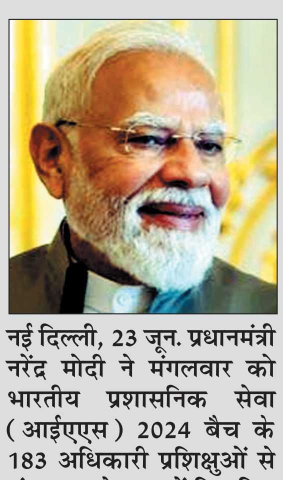

नई दिल्ली, 23 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए उन्हें विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया.

प्रधानमंत्री कार्यालय (सेवा तीर्थ) में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि दो वर्षों के फील्ड अनुभव और प्रशासनिक प्रशिक्षण के बाद युवा अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचे हैं, जहां उनके फैसले न केवल उनके करियर बल्कि करोड़ों नागरिकों के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसेवा की वास्तविक परीक्षा ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने में है. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से नवाचार, उद्देश्यपूर्ण कार्यशैली और नागरिक-केंद्रित शासन के माध्यम से राष्ट निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासनिक फाइलों को केवल कागजी प्रक्रिया न समझें, बल्कि यह याद रखें कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं, समस्याएं और जीवन जुड़े होते हैं. उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए अधिकारियों से हर निर्णय के केंद्र में नागरिकों को रखने और शासन को संवेदनशील, जवाबदेह तथा समावेशी बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बड़े विकासात्मक लक्ष्यों को विभागीय सीमाओं में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है, जिससे स्थायी और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें.

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रत्येक नीति और प्रशासनिक निर्णय देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देने वाला होना चाहिए.

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार एवं अवसर सृजन को वर्तमान समय की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया।उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में शासन व्यवस्था प्रक्रिया-आधारित मॉडल से परिणाम-आधारित मॉडल की ओर बढ़ी है. डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और तकनीक की मदद से सेवा वितरण अधिक पारदर्शी और सुगम हुआ है. डेटा आधारित प्रशासन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंकड़ों को केवल संख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें करोड़ों लोगों के जीवन, चुनौतियों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब मानना चाहिए.